कार्य समाप्त हो गया है। प्रथम छः रिपोर्टों के तैयार हो जाने के बाद इन रिपोर्टों के लिखने का कार्य शुरू किया जायेगा, शेष क्षेत्रों में, क्षेत्रीय कार्य अभी तक चल रहा है।

गोरखपुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

1698. **श्री गोलहू प्रसाद** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आज 11 जनवरी, 1970 के अंक में छपे समाचार के अनुसार गोरखपुर में टेलीफोन कार्यालयों की संख्या बढ़ कर लगभग 1500 हो गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि एक संसदसदस्य ने इस संदर्भ में संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री को पहले भी एक पत्र लिखा था;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब टेलीफोन मालिकों की संख्या 1000 हो जाये तो एक स्वचालित केन्द्र खोलने की सरकार की नीति है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) गोरखपुर में इस समय 1,350 टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं। शीघ्र ही 144 नए कनेक्शन दिए जायेंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) हर एक स्थान के मामले पर वहां उपयुक्त भवन बनाने के लिए भूमि की उपलब्धि और माँगों के बढ़ने के अनुसार उसके गुणावगुण के आधार पर जांच की जाएगी।

(घ) गोरखपुर में एक स्वचालित कनेक्शन खोलने का प्रस्ताव है और भूमि-अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्रवाही शुरू कर दी गई है।

खाद्यान्नों के बारे में आत्म निर्भरता

1699. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके द्वारा कुछ समय पूर्व इस बारे में दिये गए वक्तव्य के बावजूद भी वर्ष 1971 के बाद से खाद्यान्नों का आयात बन्द हो जाने की सम्भावना नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं तथा भारत खाद्यान्नों के बारे में सम्भवतः कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। आशा है कि 1971 के बाद खाद्यान्नों का रियायती आयात बन्द कर दिया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की माँगें

1700. **श्री रघुवीर शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारी अपनी मांगें पूरी कराने के बारे में काफी समय से आन्दोलन करते आ रहे हैं तथा अब उन्होंने हड़ताल करने का निश्चय किया है क्योंकि उनकी माँगें पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनकी सेवा की शर्तें सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा

सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना कर्मचारी संघ समय-समय पर मांगें करता रहा है। जनवरी 1970 में उन्होंने अनेक मांगों वाला एक परिपत्र जारी किया और साथ ही 18 जनवरी, 1970 को हड़ताल करने का इस आशय का एक नोटिस दिया कि यदि ये मांगें 25 दिनों के अन्दर-अन्दर पूरी नहीं की जाती तो कर्मचारी सीधी कार्यवाही करेंगे। 5 फरवरी, 1970 को दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारियों ने संघ से समझौते की बात की और इसके परिणामस्वरूप हड़ताल का नोटिस वापिस ले लिया गया।

(ख) और (ग). उनकी मुख्य मांगें लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को शीघ्र ही स्थाई करने, अस्थाई पदों को स्थाई पदों में बदलने, वेतन वृद्धि की स्वीकृति, चालकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने, प्रशीतन केन्द्रों में निःशुल्क वास प्रदान करने, परिवहन भेदों को जर्सियां प्रदान करने, योजना को सरकारी संगठन के रूप में जारी रखा जाए, न कि उसे निगम में परिणित किया जाए, आदि आदि से सम्बन्धित है। उपरोक्त (क) में उल्लिखित समझौते की कार्यवाही से संघ द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों पर विचार-विमर्श से समझौता हो गया था। सरकार संघ की यथा सम्भव मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयत्न कर रही है और वस्तुतः अब कोई मुख्य मांग बाकी नहीं है। 300 से अधिक अस्थाई पदों को स्थाई पदों में परिवर्तित कर दिया गया है और उनके स्थान पर सुपात्र व्यक्तियों को स्थाई किया जा रहा है। निम्न श्रेणी लिपिकों और रोकड़ लिपिकों को, जिन्हें पदों के भर्ती नियम बनाने से पूर्व भर्ती किया गया था, अब बिना टाईपिंग टेस्ट के स्थाई किया जा रहा है। प्रायः सभी पदों के भर्ती नियम या तो संशोधित कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं जिससे कि कर्मचारियों को प्रोन्नति के पर्याप्त मार्ग उपलब्ध किए जा सकें। दिल्ली दुग्ध योजना को यदि एक निगम में भी परिणित किया जाता है तो भी सरकारी नौकर की हैसियत से कर्मचारियों के मौजूदा विशेषाधिकारों को भी पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा। दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारी तथा सरकार कर्मचारियों की सही मांगों के लिए सदा सचेत है तथा सहानुभूति पूर्वक रवैया रखते हैं और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए यथा व्यवहारिक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

I.T.I. Trainees

1701. DR. RANEN SEN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of trainees passed out during the last three years from various Industrial Training Institutes located in the States ; and

(b) the number of those absorbed for apprenticeship training in the public Sector Undertakings and Large Scale undertakings ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI D. SANJIVAYYA : (a)

Year	*Number of trainees passed out*
1967	63,093
1968	56,740
1969	50,917

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Propagation of Casteism Over A.I.R.

1702. SHRI P. GOPALAN :
SHRI K.M ABRAHAM :
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :
SHRI P. RAMAMURTI :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state ;